Kashmir as well as drought prone area earlier known as KBK (Koraput, Bolangir and Kalahandi) Districts of Orissa is currently under consideration of the Government.

Central Pool Assistance to North-Eastern States

434. SHRI KHAGEN DAS: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have decided to earmark 10 percent of the Budget of the Government of India for the North-Eastern States; and

(b) if so, what is the total • amount spent, State-wise, by the various departments of Government of India in pursuance of this decision?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) and (b) A Non-lapsable Central Pool of Resources has been constituted for the North East and Sikkim from out of unspent amount(s) from 10% of the Budget(s) of various Union Ministries/ Departments earmarked for these State. The total amount spent, State-wise, by the concerned Ministries/Departments in the North East would be known only after the financial year is over.

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रति नौकरशाही का असहयोगात्मक रवैया

435. **श्री ईश दत्त यादव** :

चौ. हरमोहन सिंह यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि नौकरशाही की लाल फीताशाही संसद सदस्य क्षेत्रीय विकास निधि (एम पी एल ए डी एस) के तहत संचालित होने वाले कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वर्षो के दौरान सरकार ने नौकरशाहो के इस असहयोगात्मक रवैये के खिलाफ कोई कार्रवाई की हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अवांछनीय क्रियाकलाप से छुटकारा पाने के लिए क्या कार्रवाई की गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) एमपीलैड्स से संबंधित कार्यो के कार्यान्वयन में विलंब की कुछ शिकायतें सरकार के संज्ञान में लाई गई हैं। जब कभी ऐसी शिकायत प्राप्त होती हैं, उसे तत्संबंधी नियमों के अनुसार संबंधित अधिकारियों के विरूद्व उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया जाता है। राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वे मार्गदर्शी सिद्वांतों के दृढ़ अनुपालन हेतु क्लेक्टरों तथा कार्यकारी अभिकरणों के लिए निर्देश जारी करें।

Release of second crore under MPLADS

436. SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) by when the second crore of rupees for MPLADS of the current financial year will be released; and

(b) the reasons for delay in release of the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) and (b) Action has been taken for obtaining additional budget provision for releasing the funds at enhanced rates of Rs. two crores per MP from the year 1998-99.